

प्रेषक,

नवीन चन्द शर्मा,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन,

मंत्रा में,

निबन्धक,

सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड

भलोका।

राहगारिता, गन्ना एवं चीनी अनुभाग-न वेहणदूः दिनांक: १० दिसंबर 2005

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 के लिए लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी०पी०एल० परिवारों को सहकारी खण्डों पर राजकीय अनुदान के अन्तर्गत वित्तीय स्वीकृति।

महाराज,

उपर्युक्त विषयक अपर निबन्धक सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड के पर नंख्या 3205/निल००/उत्तराखण्ड 2005-06 दिनांक 22 सितंबर 2005 के लिए में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2005-06 में लघु एवं सीमान्त कृषकों तथा बी०पी०एल० परिवारों को सहकारी खण्डों पर राजकीय अनुदान के रूप में रूपये 61.29 लाख (रु० इक्कमठ लाख अनुदान हजार) की श्री राज्यपाल महाराज द्वारा दिए गए अनुदान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हैं।

१. उक्त अनुदान का उपरोक्त शासनादेश संख्या-233/2005/XIV-1/2005, दिनांक 28 अप्रैल 2005 में दृल्लिखित शर्तों के अनुसार ही किया जायेगा।

२. अपर निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड स्वीकृत अनुदान के आहरण की सुन्नत महालेखाकार (लंखा) कार्यालय उत्तराखण्ड की प्रति के साथ कोपागार का जाग, आठवर लंखा, लंखाशीर्पक तथा आहरण की लिखि सहित सूचित करेंगे।

३. इस शासनादेश में दिला द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों पर अनुपालन विभागों/उपकामों में दैनाल वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लंखापिकारी, जिसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे, यदि निर्धारित शर्तों का किसी प्रकार का विचलन हो तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक अदि का धावित होंगा जि उसके हारा मामले जी सुचना पूर्ण विवरण सहित तुरन्त वित्त विभाग को दी जाय।

४. उक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि उक्त अनुदान योवत् इसी योजना के अन्तर्गत स्थोकृत खण्डों पर देव व्यवहार के राजकीय अंदा के अनुदान के रूप में ही व्यष्ट/प्रति पूर्ति जी जाय, तथा किसी एम्ब व्यार्थ/मद पर अनुदान व्यव न को जाय, जो योजना पर स्वीकृत नहीं है।

५. स्वीकृत अनुदान का उपरोक्त निहित रूप से उन्हीं मध्ये पर किया जाय, जिसके लिए स्वीकृत नहीं जा रही है, तरि उक्त उपरोक्त अन्यत्र अन्यका किसी अन्य मद में किया जाता है तो सम्बन्धित अधिकारी इसके लिए लद्दिकाल रूप से दिमेंदार होंगे तथा उनसे अद्वायिकूल व्यय जी व्यसूली को जायगी।

६. उक्त स्वीकृत अनुदान का योजनापार व्यय विवरण प्रत्येक माह का उसके अन्तर्गत माह को २ तारीख तक थी.एम.-१३ पर नियमित रूप से वित्त विभाग, शासन तथा महालेखाकार की विज्ञाना सुनिश्चित करें।

७. उक्त जान शासन के वर्तमान सुरक्षात् आदर्शों/निर्देशों के अनुसार किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त अनुदान कियो एम्ब व्यार्थ/मद पर व्यय न को जाय, जिसके लिए

५ हस्तागुस्तिका तथा बजट भिन्नभल के अन्तर्गत शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्थोर्हता अपर्कित वर्तीय हस्त गुल्जिका मैं उल्लिखित सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जाय।
उक्त व्यव वर्तमान वित्तीय वर्ष 2005-06 के अनुदान संख्या-18 के अन्तर्गत लेखारोपित-
सहकारिता-आयोजनागत-००-८००-अन्य व्यय-१३-सहकारी सहभागिता योजना-००-२०-सहायक
न/असाधान/सज सहायता के नामे डाला जायगा।

यह आदेश विभाग की अशासकीय पत्र संख्या- ४८ /वित्त (व्यव नियमण) ३-४/२००४/दिनांक १९.११.२००५ मे जाता उनको सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

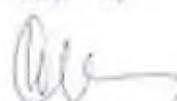

(नन्द शर्मा)
सचिव,

- ६०९ (१)/ न११-१/२००५-१(१)/२००५/तददिनांक.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यपाली हातु प्रेषितः

१. गहालेयाकार, लेखा एवं हक्कदारी, अंतर्राष्ट्रीय पोर्टर्स बिल्डिंग, साहानपुर गांड, देहरादून,
२. अयुक्त, कुमाऊँ मण्डल, नीमीताल/गढ़वाल मण्डल, बैड़ी,
३. सचिव, कृषि उत्तराखण्ड शासन।
४. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
५. अपर नियन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
६. कांगापिकारी/विलाधिकारी, उत्तराखण्ड अल्मोड़ा।
७. नियंत्रक, कौशामार एवं यिला, २३ लक्ष्मी गांड देहरादून।
८. एकट नियन्त्रण प्रकांप्ट उत्तराखण्ड शासन।
९. नियंत्रण एम०आई०स००० सचिवालय परिसर उत्तराखण्ड।
१०. घजट राजकीय नियंत्रण एवं संसाधन, सचिवालय देहरादून।
११. सचिव विलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
१२. गांड फाईल।

आज्ञा से,


(केशव दत्त)
अपर सचिव,